International Journal of Business Economics and Management Research
Vol. 10, Issue 8, August 2019 Impact Factor: 4.963 ISSN: (2229-4848)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में आर्थिक विषमता एक चुनौती

गिरजा शंकर गुप्ता
सहा. प्राध्यापक वाणिज्य
दुर्गा कॉलेज रायपुर

सारांश

भारत में आर्थिक नियोजन कई सामाजिक.आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीकरण (Concentration of Economic Powers) बढ़ा है। क्षेत्रीय विषमताएँ तथा बेरोजगारी बढ़ी है। सबसे हास्यस्पद तो यह हुआ कि योजना प्रक्रिया तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ उसी निजी क्षेत्र को पहुंचाए जिस पर अंकुश लगाकर सरकार अपने घोषित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का सपना देख रही थी। लेकिन अर्थशास्त्रीयों का मत है कि बाजार की शक्तियों पर काबू नहीं रखा जाय तो आर्थिक विषमताएँ बढ़ती है। जिसके पास अर्थशक्ति है वह और भी शक्तिवान होता जाता है। उत्पाद की प्राथमिकताएँ भी बदल जाती हैं। अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर होता है। समाज में शोषण बढ़ जाता है। अतः बाजार की शक्तियों पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। परन्तु भारतीय अनुभव बताता है कि सरकारी नियंत्रणो ने बाजार की शक्तियों को और भी जर्जर बनाया है। नियंत्रण सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन बने, इसके लिये यह आवश्यक है कि नियन्त्रण की मशीनरी यानी प्रशासन सक्षम तथा मजबूत हो और भ्रष्ट नहीं हो। पर ऐसा हो नहीं पाया। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमता ने आर्थिक प्रबन्ध का काम कर दिया। यानी बाजार की शक्तियों से जो लाभ मिल सकता था, वह भी नहीं मिला तथा सरकारी नियन्त्रण को सामाजिक नियन्त्रण समझने की भूल से एक ऐसा सामाज अस्तित्व में आ गया, जो मूलतः भ्रष्ट था।

प्रस्तुत शोध पत्र को निम्न शीर्षकों में बांटकर अध्ययन करेगें।

भारत में आर्थिक विषमता के विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया गया है

(1) वैयक्तिक आय विषमताएँ (Disparities in Personal Incom) : यद्यपि भारत में वैयक्तिक आय वितरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के ऑकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है लेकिन समय.समय पर अनेक विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में वैयक्तिक आय वितरण में बहुत अधिक विषमताएँ विद्यमान हैं। हम प्रतिदिन ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से इतनी आय अर्जित कर पाते हैं कि उनका न्यूनतम गुजर बसर हो सके। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी आय अत्यधिक होती हैं तथा उनके पालतू कुत्तो की

International Journal of Business Economics and Management Research
Vol. 10, Issue 8, August 2019 Impact Factor: 4.963 ISSN: (2229-4848)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

देखभाल पर इतना खर्च किया जाता है कि उतना एक आम आदमी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता।

(2) उपभोग सम्बन्धी (Disparities in Consumption) :- भारत में उपभोग सम्बन्धी विषमताएँ भी बड़े पैमाने पर विद्यमान हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उपभोग स्तर में जमीन आसमान का अन्तर है। जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा, आदि सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों में आम आदमी को अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरी ओर अनेक ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी कोई विशेष विकास नहीं हुआ हैं। लाखों ग्रामीण व्यक्तियों को अकाल की स्थिति में प्रतिवर्ष ऐसे स्थानों पर पलायन करना पड़ता है जहाँ उन्हें स्वयं तथा अपने मवेशियों के लिये पानी, भोजन व चारा आदि मिल सके। गत 20.25 वर्षों में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच उपभोग सम्बन्धी विषमताएँ बहुत अधिक बढ़ी हैं। विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report) 2016–2017 में भारत में उपभोग व्यय में भिन्नता को **दर्शाया गया है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है –**

परिवारों के समुह (नीचे से)		व्यय का प्रतिशत	परिवारों का स्वंयी प्रतिशत	व्यय का संचयी प्रतिशत
निम्नतम	20%	9.2	20	9.2
दुसरा	20%	13.0	40	22.2
तीसरा	20%	16.8	60	39 .0
चौथा	20o/o	21 .7	80	60.7
चोटी के अथवा सर्वोच्च	20o/o	39.3	100	100.0

Source: World Developmen t Report 2016-17

भारत में परिवार–समुहों के अनुसार व्यय 2016–2017

तालिका से स्पष्ट है कि नीचे के 20 प्रतिशत परिवारों द्वारा कुल व्यय का 9.2 प्रतिशत भाग खर्च किया जाता है। परिवारो का संचयी प्रतिशत व व्यय का संचयी प्रतिशत देखने से पता चलता है कि देश में 60 प्रतिशत परिवार कुल व्यय का 39 प्रतिशत भाग व्यय करता हैं जब की चोटी के 20 प्रतिशत परिवार कुल व्यय का 39.3 प्रतिशत भाग व्यय करते हैं। इस तालिका से भारत में विद्यमान उपभोग व्यय का विषमताओं का पता चलता हैं।

(3) प्रादेशिक आर्थिक विषमताएँ (Regional Economic Disparities):– भारत में विषमताओं का एक स्वरूप प्रादेशिक आर्थिक विषमताएँ भी हैं। भारत के कुछ राज्य जो प्राकृतिक दृष्टि से सम्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है जबकि पिछड़े राज्यों

में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। नेशनल कौंशिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER) के एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्रो में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

(4) धन एवं सम्पत्ति विवरण में असमानताएँ (Disparicities in Distribution of Wealth and Property) :– हमारे देश में धन एवं सम्पत्ति के वितरण में भी काफी असमानताएँ पायी जाती हैं। धन एवं सम्पत्ति के असमान वितरण की विषमता में वृद्धि की है और अधिक स्थायी बनाया है। स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए विभिन्न भू–सुधारो के बावजूद आज भी देश में लाखो बड़े किसान हैं जिनके पास बेनामी जमीन है। दूसरी तरफ सीमान्त किसान, भूमिहीन किसान तथा कृषि श्रमिको की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 59 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर तक भूमि है तथा कुल भूमि में उनका हिस्सा मात्र 14.9 प्रतिशत है। शहरी सम्पत्ति के वितरण में भी काफी विषमताएँ हैं प्रत्येक शहर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगो का उपहास उड़ाती हुई गगनचुम्बी महलनुमा इमारतों के निर्माण की होड़ सी लगी हुई है।

भारत में आर्थिक विषमताओं के कई कारण हैं। वैयक्तिक आय तथा उपभोग में विषमताएँ योग्यता अवसर कुशलता सम्पत्ति स्वामित्व तथा उत्तराधिकार आदि पर निर्भर करती है। जबकी क्षेत्रीय विषमताएँ प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता विकास की स्थिति साहस आदि पर निर्भर हैं।

भारत में आर्थिक विषमताओं के कुछ प्रमुख कारणो का अध्ययन :–

1. निर्धनता (Poverty) :– देश में वैयक्तिक आय तथा उपभोग सम्बन्धी विषमताओं का एक मूल कारण है। योजनाबद्ध विकास के पाँच दशकों के बाद भी लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी के रेखा (Poverty Line) से नीचे है तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं।

2. अवसरो की असमानता (Inequality of Opportunities) :– जिन व्यक्तियों को अच्छे अवसर मिल जाते हैं, उनकी आय एवं सम्पत्ति में खूब वृद्धि हो जाती है। जबकि वे व्यक्ति जो सुअवसर से वंचित रह जाते हैं, निर्धन बने रहते हैं। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ धनी वर्ग के साधरण बुद्धि वाले बच्चे अवसर मिलने से आर्थिक प्रगति कर जाते हैं, जबकि कुशाग्र बुद्धि वाले परिश्रमी एवं योग्य बच्चे अवसर के अभाव में पिछड़ जाते है।

3. उत्पादन के साधनो का असन्तुलित वितरण (Inequitable distribution OD the Means of Production) :– भारत में उत्पादन के साधनो के असन्तुलित वितरण के कारण आय तथा धन की विषमताएँ बनी हुई है। उत्पादन के दो महत्वपूर्ण साधनों–भूमि तथा पूँजी पर छोटे से

वर्ग का अधिकार होने के कारण न केवल आर्थिक विषमताएँ विद्यमान हैं बल्कि इससे विषमताओं में वृद्धि भी हो रही है।

4. जनसंख्या वृद्धि (Population Growth) :– गत 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि में जो विस्फोटक वृद्धि हुई है, वह भी देश में आर्थिक विषमताओं के वृद्धि के एक कारण है। यह वृद्धि मुख्य रूप से समाज के निम्न–भव्य एवं दरिद्र वर्गो में हुई है। उनकी आय के स्तर पहले ही कम थे और परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने से उनकी आय और भी घट गई है तथा वे निर्धनता रेखा के छोर पर पहुंच गए।

5. व्यावसायिक भिन्नता (Occupational Differences) :– व्ययवसायिक भिन्नता भी आर्थिक विषमताओं का एक कारण है। अधिक जोखिम वाले व्यवसायों से अधिक आय प्राप्त होती है जबकि साधारण व्यवसाय या नौकरी से कम आय प्राप्त होती है।

6. मुद्रा स्फीति (Inflation) :– भारत में गत 50 वर्षों से लगातार मुद्रा स्फीति में वृद्धि हो रही है। मुद्रा स्फीति के कारण स्थिर आय वर्ग के लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है। जबकी भूमिपतियों व्यापारियों उद्योगपतियों सटोरियों आदि की आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इससे आय व सम्पत्ति का धनिको के पक्ष में हस्तान्तरण होने लगता है तथा विषमताओं में वृद्धि होती है।

7. कर अपवंचन (Tax Evasion):– कर अपवंचन (करों की चोरी) भी आर्थिक विषमताओं का एक कारण है। उच्च मध्य तथा धनी वर्ग के लोग कर अपवंचन करते हैं जिससे वे और भी धनी बन गये हैं। भारत में एक मोटे अनुमान के अनुसार वर्तमान में 80 हजार करोड़ रू. से अधिक का काला धन जमा है। यह धन समाज के मुट्ठी भर लोगों के पास हैं। इससे धन तथा सम्पत्ति की विषमताएँ और बढ़ती हैं।

8. बेरोजगारी (Unemployment) :– बेरोजगारी आय के असमान वितरण के प्रमुख कारणों में से एक है। नियोजन के 56 वर्ष बाद भी देश की बेरोजगारी कम नहीं हुई है। अपितु प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति पंजीकृत बेरोजगार हैं। उत्पादन के साधनो का अनुचित वितरण पूँजी गह प्रौद्योगिकी अपर्याप्त विकास आदि कारण बेरोजगारी के लिये उत्तरदायी हैं। परिणामस्वरूप दरिद्र और भी दरिद्र बनते जा रहे हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमताओं को पूरी तरह से समाप्त करना सम्भव नही है। हाँ आर्थिक विषमताओं में कमी अवश्य ही लाई जा सकती है। आय तथा धन की विषमताएँ घटाने के उद्देश्य से अपनाए गये उपायों की प्रकृति पुर्नवितरणात्मक होनी चाहिए। ऐसे उपाय काम में लेने चाहिए जिससे उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो, आर्थिक संकेन्द्रण घटे और जनसाधारण की आय बढ़े।

आर्थिक विषमताओं में कमी लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं –

1. भूमि सुधार (Land Reforms) :– भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करके अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। इस अतिरिक्त भूमि को कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसाों में बॉट देना चाहिए। निर्धन किसानों को सस्ती एवं पर्याप्त ऋण सुविधाएँ, अच्छे बीज उर्वरक उपलब्ध कराने चाहिए तथा कृषि उत्पादन के विपणन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे निर्धन किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा विषमताएँ कम होंगी।

2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment Opportunities) :–रोजगार के अवसरो में वृद्धि की जानी चाहिए। जहा तक सम्भव हो श्रम तकनीकी वृद्धि को अपनाना चाहिए ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके। कृषि अधारित एवं ग्राम उद्योगों की स्थापना तथा स्वरोजगार (Self- Employment) हेतु प्रशिक्षण वित्त आदि उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसरों में सम्भव है।

3. न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages):– आय वितरण सम्बन्धित विषमताओं को कम करने के लिए आवश्यक है का अर्थव्यवस्था के संगठित दोनों ही के क्षेत्रों के लिए मजदुरी सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि औद्योगिक तथा कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अवश्य ही मिल सके ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

4. जनसंख्या नियन्त्रण (Population Control) :– भारत में आज भी 2.14 प्रतिशत वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही हैं। आर्थिक विषमताओं में कमी लाने के लिए जनसंख्या नियन्त्रण सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जनता को यह समझाया जाना चाहिए की बड़े परिवारो का तात्पर्य है – प्रति व्यक्ति कम आय। अतः प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन के तरीके अपनाने की जरूरत है। शिक्षा के प्रसार, प्रचार एवं सस्ते व प्रभावशाली गर्भनिरोधकों के प्रभाव द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण की जा सकती है।

5. सामाजिक सुधार (Social Reforms) :– सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे सामाजिक सुधार हो एवं कुरीतियों पर रोक लगे। मृत्यु–भोज, मुंडन संस्कार आदि अनुत्पादक कार्यों पर किये जाने वाले व्यय पर रोक लगानी चाहिए। अंधविश्वास तथा कुरूतियों के कारण अधिकांश निर्धन लोग इन अनुत्पादन कार्यों पर अनाप सनाप खर्च करते है तथा जीवन पर्यन्त गरीबी व ऋणग्रस्तता के शिकार बने रहते हैं।

6. मुद्रा– स्फीति पर नियन्त्रण (Control on Inflation) :– आय तथा सम्पत्ति का अमीरों के हित में हस्तान्तरण रोकने तथा निर्धनों को महंगाई की मार से बचाने के लिए मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण करना नितान्त आवश्यक है। आर्थिक विषमताओं में कमी लाने के लिये मुनाफाखोरी तथा कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

7. पिछड़े क्षेत्रों का विकास (Development of Backward Areas) :– आर्थिक विषमताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास अति आवश्यक हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए राजकोषीय एवं अन्य छूटे प्रदान करके उद्यमियों को आकर्षित करना चाहिए। यदि कच्चा माल उपलब्ध हो तो सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करना चाहिए। यदि कच्चा माल उपलब्ध हो तो सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने चाहिए। परिवहन, सिचाई, विद्युत् आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए तथा पिछड़े क्षेत्रों में कृषकों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए।

8. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) :– आय तथा धन की विषमताएँ कम करने में राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रगतिशील करारोपण (Progressive Taxation) के द्वारा धनवानो की आय व सम्पत्ति का कुछ हिस्सा राजकोष में लाया जा सकता है तथा इस राशि को गरीबो पर व्यय करके उनकी आय बढ़ायी जा सकती है। काला धन निकलवाने और कर अपवंचन रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए तथा निम्न माध्यम एवं दरिद्र वर्गों पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम किया जाना चाहिए। इससे आर्थिक विषमताओं में कमी लायी जा सकेगी।

निष्कर्ष

यद्यपि सरकार ने आर्थिक विषमताएँ घटाने के लिए अनेक उपाय काम में लिए हैं। परन्तु फिर भी विषमताएँ घटने की बजाय बढ़ रही हैं। विषमताओं को कम करने के लिए कानून का सही क्रियान्वन आवश्यक है साथ ऐसे उपायों पर जोर देना जरूरी है जिनसे रोजगार अवसरों में वृद्धि हो तथा निर्धनों की आय बढ़ सके। आय तथा धन संबंधी विषमताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति में सुधार करना अत्यंत अवश्यक है। कालेधन में कमी लाते हुए कर अपवचंन को रोकने हेतु कठोर कानून बनाये जाने चाहिए जिससे निर्धन लोगों की आय में वृद्धि हो और आर्थिक विषमता को दूर करने में सहायक हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रूद्र दत्त के. पी. सुन्दरम् भारतीय – अर्थव्यवस्था नवीन संस्करण, एस चंद्र पब्लिकेशन।
2. आर्थिक विकास एवं नियोजन – एस.पी. सिंह संस्करण 2010, एस. चंद्र पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. श्री वी. सी. सिंहा – व्यावसायिक पर्यावरण साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा।
4. आर्थिक समीक्षा 2008–2009 भारत सरकार
5. डॉ. विमल कुमार जैन – भारत में आर्थिक नियोजन कालेज बुक डिपो, नई दिल्ली